Result Mitra Daily Magazine

स्वच्छ भारत मिशन

➢ हालिया संदर्भ :

- नेचर प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन के बाद शिशु और बाल मृत्यु दर (0-5 वर्ष) में तेजी से कमी आई है।
- रिपोर्ट के अनुसार समग्र बेहतर स्वच्छता स्थितियों ने भारत में सालाना 60,000-70,000 शिशु मृत्यु को रोका है।

➢ मुख्य बातें :

- अध्ययन में 35 राज्यों/UTs के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे एवं 640 जिलों से जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षणों से प्राप्त मृत्यु संबंधी डेटा का प्रयोग किया गया।
- अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में 5.4 मिलियन बाल एवं शिशु मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, जिसमें से लगभग 10.8 लाख बच्चे भारत से संबंधित होते हैं।
- 2003-2020 के बीच शिशु मृत्यु दर में गिरावट देखी गई है, जो 2015 के बाद उल्लेखनीय रूप से कम हुई है।
- 2003 में एक जिले में शौचालय कवरेज 40% से कम था, जो 2020 में बढकर 60% हो गया।
- 2003 में अधिकांश जिलों में शिशु-मृत्यु दर 48.9 के औसत के साथ 60 (प्रत्येक 1000 जीवित बच्चों) था।

- ऐसे राज्यों में राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, WB, ओडिशा, UP, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, असम हिमाचल प्रदेश शामिल थे।
- रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक कई जिलों में बाल मृत्यु दर 30 से नीचे आ गई, जबकि समग्र मृत्यु दर 23.5 के औसत पर आ गया।
- तमिलनाडु, UP, तेलंगाना, महाराष्ट्र, MP, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड जैसे राज्यों में शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट दर्ज की गई है।

➢ स्वच्छ भारत मिशन :

- 2 Oct 2014 को जन-आंदोलन के रूप में शुरूआत,
- 2019 तक स्वच्छ भारत का निर्माण करना लक्ष्य,
- शहरी क्षेत्र में क्रियान्वयन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में मिशन का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा।

➢ मिशन के घटक :

❖ निर्मल भारत अभियान :

- गाँवों को ODF (खुले में शौच मुक्त बनाना) लक्ष्य
- 2020 तक 100 मिलियन से ज्यादा घरों में शौचालय की सुविधा प्रदान की गई तथा 6 लाख से ज्यादा गाँवों को ODF घोषित किया गया।

❖ शौचालय निर्माण :

- इस कार्यक्रम के तहत सभी BPL परिवारों एवं APL श्रेणी में शामिल SC, ST, लघु एवं सीमांत किसान, दिव्यांगों एवं महिला-मुखिया वाले परिवारों को शौचालय निर्माण के लिये 12000 रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है।
- इसमें केन्द्र की हिस्सेदारी 9000 (75%) जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 3000 (25%) है, जबकि पूर्वोत्तर एवं विशेष राज्यों के लिये यह अनुपात 90:10 (केन्द्र एवं राज्य) है।

❖ राष्ट्रीय स्वच्छता कोष :

- इसके तहत निगम सामाजिक दायित्व के तहत वित्त प्राप्त कर इसका उपयोग स्वच्छता स्तर को बढाने के लिये किया जाता है।

Result Mitra TM

❖ गोबर-धन :

- 2018 में इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लांच किया गया था, जिसका उद्देश्य जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट को संपीडित बायोगैस में परिवर्तन करना है ताकि किसानों की आय बढ सके।

❖ स्वच्छ विद्यालय मिशन :

- शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य स्कूलों में लडके-लडकियों के लिये अलग-अलग शौचालय उपलब्ध करवाना है।

➢ ODF की श्रेणियाँ :

1. ODF : यदि दिन के समय कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन खुले में शौच नहीं करता है तो इस क्षेत्र को ODF के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

2. ODF+ : यह प्रमाणन किसी शहर को तब दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच नहीं किया जाता है, साथ ही उस शहर के सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहे हों।

3.ODF++ : ODF+ प्राप्त किसी शहर को इस श्रेणी का प्रमाणन तब दिया जाता है, जब वहाँ मल/अपशिष्ट/नालियों का सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन किया जाता हो एवं ऐसे अपशिष्टों को जल-निकायों का खुले क्षेत्र में प्रवाहित न किया जाता हो।

➢ ODF के संकेतक :

1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
2. मलयुक्त कीचड प्रबंधन
3. जैव-निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
4. ग्रे-वाटर प्रबंधन

➢ शीर्ष 5 राज्य (ODF के मामले में)

1. तेलंगाना
2. तमिलनाडु
3. ओडिशा
4. UP
5. हिमाचल प्रदेश

Result Mitra TM